IJAER/Sep-Oct -2022/Volume-11/Issue-5 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संस्थापक डॉ0 केशव बलिराम हेडगेवार

पुनीत कुमार राजपूत

शोधार्थी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल

डॉ. गुरेंद्र सिंह

सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान

कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल

अमूर्त

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भारत के राजनीतिक जीवन और शिक्षा जगत में व्यापक और गहन बहस का विषय रहा है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि किसी भी संगठन के संस्थापक के जीवन और वैचारिक स्वभाव की व्यापक समझ उस संगठन के सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दृष्टिकोण और संस्कृति को सही मायने में समझने के लिए आवश्यक है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आरएसएस और उसके संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार एक दूसरे के पर्याय हैं। किसी भी संगठन और उसकी विचारधारा के साथ सहमति या असंगति, बेशक, लोकतांत्रिक राजनीति का एक आंतरिक हिस्सा है, लेकिन एक ऐसे संगठन के संस्थापक की अज्ञानता, जिसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है, केवल गलत सूचना को जन्म देता है जो दुर्बल करने की ओर ले जाता है। गलतफहमी। इसका परिणाम वैचारिक आंदोलनों और उनके द्वारा तय की गई यात्रा का अधूरा और यहां तक कि दोषपूर्ण मूल्यांकन है, जो राष्ट्रीय जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। दुख की बात है कि डॉक्टर हेडगेवार का जीवन ऐसी कई भ्रांतियों का शिकार है, जिनमें से कई जानबूझकर की गई हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से उनका कथित अलगाव ऐसी ही एक भ्रांति है। यहाँ प्रस्तुत तथ्य यह प्रकट करने में सहायक हैं कि ऐसी भ्रांतियाँ वास्तविकता से कितनी दूर हैं।

कीवर्ड्स : डॉ. केशव बालीराम हेडगेवार , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)

परिचय

भारत की आजादी के पहले पांच दशकों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में आरएसएस की भूमिका कोई मुद्दा नहीं थी। आरएसएस के आलोचकों के लिए यह मुद्दा तब गरमा गया जब अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉ. केशव बलिराम की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया 18 मार्च 1999 को एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार । शम्सुल इस्लाम जैसे कुछ लेखकों का तर्क है कि आरएसएस ने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में कभी हिस्सा नहीं लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एक प्रमुख नेता सीता राम येचुरी ने अपने लेख "हिंदू राष्ट्र क्या है?" में कहा है कि "इसने स्वतंत्रता संग्राम का वस्तुतः बहिष्कार किया और कई बार विरोध किया।" लगभग इसी तरह के दावे सुमित सरकार ने भी किए थे (मार्क्सवादी इतिहासकार) और कई अन्य कम्युनिस्ट नेता और भारत के कुछ कांग्रेस नेता। ऐसा माना जाता है कि इन नेताओं और इतिहासकारों ने सच्चाई से छेड़छाड़ की है, तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा है और ऐतिहासिक घटनाओं की गलत व्याख्या की है। एक संगठन या किसी व्यक्तिगत स्वयंसेवक के रूप में आरएसएस ने कभी

भी औपनिवेशिक सरकार के साथ सहयोग या एकीकरण नहीं किया। यहां तक कि एक मार्क्सवादी इतिहासकार, बिपिन चंद्रा ने भी इस तथ्य को विकृत तरीके से स्वीकार किया, जब उन्होंने लिखा, " हेडगेवार कभी भी औपनिवेशिक शासन के साथ एकीकृत नहीं हुए।"

1 डॉ. हेडगेवार , एम.एस. गोलवलकर, वी.डी. सावरकर, आदि जैसे कई नेता कट्टर राष्ट्रवादी थे, औपनिवेशिक शासन के दौरान कारावास का सामना करना पड़ा और आरएसएस की सभी शाखाओं को 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर पूर्ण स्वतंत्रता पर कांग्रेस के संकल्प का जश्न मनाने का निर्देश दिया। इसके कार्यालय। आरएसएस के अधिकांश स्वयंसेवकों ने न केवल नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया बल्कि देश के विभाजन के दौरान और बाद में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान लोगों की मदद भी की।

केशव बलिराम हेडगेवार

भारतीय राष्ट्रवादियों ने खुद पर शासन करने की क्षमता और देश के भविष्य के विकास में विश्वास हासिल कर लिया था। बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, दामोदर जैसे नेता चापेकर , श्यामाजी कृष्ण, वीडी सावरकर, केशव बलिराम हेडगेवार आदि ने स्वाभिमान के संदेश का प्रचार किया और राष्ट्रवादियों से भारतीय जनता के चरित्र और क्षमता पर भरोसा करने को कहा। जनता की ताकत में उनका गहरा विश्वास था, और उन्होंने सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से स्वराज हासिल करने की योजना बनाई। उन्होंने जनता के बीच राजनीतिक काम के लिए राजनीतिक और जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई के लिए दबाव डाला। उन्नीसवीं सदी के आखिरी दशक और बीसवीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र हिंदू राष्ट्रवाद के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा। विशेष रूप से, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव के साथ-साथ दो समाचार पत्रों को प्रकाशित करके अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया, एक मराठी में केसरी और दूसरा अंग्रेजी में मराठा कहा जाता है। वह सबसे पहले महाराष्ट्र के किसानों को भू-राजस्व के भुगतान को रोकने के लिए कहने वाले थे, जब उनकी फसल अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण विफल हो गई थी। उन्होंने स्वदेशी के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया जब वायसराय एल्गिन ने भारतीय कपड़ों पर उत्पाद शुल्क लगाया।

नतीजतन, अंग्रेजों ने 1897 में तिलक को गिरफ्तार कर लिया और उन पर औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ घृणा और असंतोष फैलाने का आरोप लगाया, जिसके कारण प्लेग अधिकारी मिस्टर रैंड और मिस्टर आयर्स्ट की हत्या कर दी गई। उन्हें अठारह महीने तक जेल में रखा गया। 5 दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद, डॉ. बालकृष्ण शिवराम मुंजे , जो नागपुर में युवा कट्टरपंथियों के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में उभरे, तिलक के बहुत बड़े प्रशंसक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। हेडगेवार ने भी उनके संरक्षण का आनंद लिया। इसके अलावा, नागपुर के एक स्कूल शिक्षक अंतजी काले ने 1902 में न केवल प्लेग प्रभावित लोगों की राहत के लिए धन एकत्र किया, बल्कि हेडगेवार सहित युवा लड़कों को भी चंदा-संग्रह अभियान में डुबकी लगाने के लिए प्रेरित किया। नीलांजन मुखोपाध्याय लिखते हैं,

युवा लड़के (हेडगेवार) ने अपने पड़ोस का दौरा करना शुरू किया और धार्मिक सभाओं और त्यौहारों में प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ एक पैसे का दान करने के लिए कहा। उस समय के विपरीत जब उन्होंने अपने दोस्तों को स्थानीय मोर्चे पर शिवाजी के झंडे को फहराने के लिए प्रोत्साहित किया था, केशव की पैसा फंड पिच एक बड़ी पहल थी और इसका उद्देश्य औसत गृहस्थ को स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का हिस्सा बनाना था। 20 जुलाई 1905 को, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने का आदेश जारी किया - 31 मिलियन की आबादी वाला पूर्वी बंगाल और असम, और 54 मिलियन की आबादी वाला शेष बंगाल, जिनमें से 18 मिलियन बंगाली और 36 मिलियन बिहारी थे और उड़िया ।

अंग्रेजों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि मौजूदा बंगाल प्रांत एक एकल प्रांतीय सरकार के लिए इसे कुशलतापूर्वक प्रशासित करने के लिए बहुत बड़ा था। लेकिन हिंदू राष्ट्रवादियों के अनुसार बंगाल के विभाजन की योजना को सांप्रदायिक आधार पर डिजाइन और कार्यान्वित किया गया था। नतीजतन, राष्ट्रवादियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया। 7 अगस्त 1905 को विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था और कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया

था। उसके बाद प्रतिनिधियों को अन्य प्रान्तों में भी आन्दोलन फैलाने को कहा गया। 16 अक्टूबर, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। एक पूर्ण हड़ताल थी, और लोग वंदे के नारे लगाते हुए गंगा नदी में स्नान करने के लिए नंगे पैर चले गए मातरम और देशभक्ति के गीत गा रहे हैं।

इसके तुरंत बाद, पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तेजी से विकसित हुआ। आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले , बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष आदि ने इस आंदोलन में भाग लिया। नागपुर में, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की भावना बंगाल से परे झाड़ी की आग की तरह फैल गई और जल्द ही यह देश के पश्चिमी भागों के तट पर पहुँच गया। डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने बहुत उत्साह और नियमित रूप से आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कहा, 'बंगाल हमारी मातृभूमि का हिस्सा है और हम इसे कभी विभाजित नहीं होने देंगे।' उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस का नेतृत्व किया बल्कि देशभक्ति गीत वंदे भी गाया मातरम की रचना बीसी चटर्जी ने की है।

वास्तव में, वह राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए विद्युतीय भाषणों से बहुत अधिक प्रेरित थे, जिन्होंने सार्वजनिक बोलने की कला सीखने के उनके संकल्प को मजबूत किया था। 10 1906 में मुस्लिम लीग के गठन के बाद, हिंदू सांप्रदायिकता भी अंकुरित होने लगी, और हिंदू सांप्रदायिकता विचारों की व्याख्या और प्रचार-प्रसार किया गया। कई हिंदुओं ने मुस्लिम सांप्रदायिकता और मुस्लिम लीग की तर्ज पर विचारों और कार्यक्रमों को अपनाने और क्रियान्वित करने का समर्थन किया । मुस्लिम सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए, 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई और इसके नेताओं ने कांग्रेस से भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं को एक राष्ट्र में एकजुट करने के लिए कहा। इसके प्रमुख नेता लाल चंद ने घोषणा की कि एक हिंदू को अपने मन में यह बात रखनी चाहिए कि वह पहले हिंदू है और बाद में भारतीय। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा का प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1915 में महाराज मणिन्द्र चन्द्र नंदी के नेतृत्व में हुआ ।

एकता और एकजुटता

इस सत्र में, हिंदू समुदाय के सभी वर्गों के बीच अधिक से अधिक एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने, उन्हें एक जैविक पूरे के हिस्से के रूप में और अधिक बारीकी से एकजुट करने और जब भी और जहां भी आवश्यक हो, हिंदू हितों की रक्षा और बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। मुंजे की सलाह पर , हेडगेवार 1910 के मध्य में चिकित्सा शिक्षा के लिए कलकत्ता चले गए। यह वह वर्ष था जब वीडी सावरकर अंडमान और निकोबार द्वीप की सेलुलर जेल में कैद थे, हेडगेवार कलकत्ता में उतरे। वहां रहने के दौरान, वे आमतौर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों से मिलते थे। इसके अलावा वे क्रांतिकारियों से बहुत अधिक प्रेरित थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने न केवल एक गुप्त क्रांतिकारी समूह युगान्तर या अनुशीलन समिति की सदस्यता ली , बल्कि समिति के कोर ग्रुप के सदस्य भी बने। 12 उसका कोड नाम ' कोकेन ' था। 1916 में कलकत्ता से नागपुर लौटने के बाद भी उन्होंने अपने मित्र भाऊजी के साथ एक क्रांतिकारी समूह की स्थापना की क्रवे और पूरे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को फैलाने की योजना बनाई। इस समूह को क्रांति दल के नाम से जाना जाता था। डॉ. हेडगेवार और कई हिंदू नेताओं ने 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए लखनऊ पैक्ट का भी विरोध किया।

1918 में, हेडगेवार ने नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया और शहर में राजनीतिक अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय मंडल की स्थापना की। उस समय, कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने सोचा था कि भारत केवल ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा हो सकता है। इस मत के विपरीत, हेडगेवार ने स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। राष्ट्रीय मंडल ने हिंदुओं को एकजुट करने और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संकल्प नामक एक हिंदी पत्रिका प्रकाशित की। उसी वर्ष, हेडगेवार ने शिवाजी की जयंती और राज्याभिषेक, गणेश चतुर्थी, शास्त्र जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय उत्सव मंडल का गठन किया । (हथियार) पूजा, विजयदशमी और संक्रांति। इन त्योहारों को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करना था।

रौलट बिलों की शुरूआत के साथ राजनीतिक माहौल गंभीर हो गया । ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह और क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए शाही विधान परिषद में दो विधेयक पेश किए। इस मुद्दे पर गांधी ने अपने आश्रम में एक सभा बुलाई। इस बैठक में वल्लभभाई पटेल, सरोजिनी नायडू, बंबई के व्यापारी उमर सोबानी ,बीजी हॉरनिमन, जमनादास द्वारकादास और ब्रिटिश मूल के राष्ट्रवादी समाचार पत्र द बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक ने सत्याग्रह प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए। जब दो रोलेट बिलों में से एक 12 मार्च 1919 को एकमत भारतीय विरोध के बावजूद पारित हो गया, तो गांधी का धैर्य जवाब दे गया। आम लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को कम करने की दृष्टि से सरकार द्वारा नया अधिनियम बनाया गया था। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से कठोर था क्योंकि इसने पुलिस को किसी भी भारतीय को बिना वारंट के तलाशी लेने या गिरफ्तार करने या बिना मुकदमे के संदिग्धों को दो साल की नवीकरणीय अवधि के लिए कैद करने के लिए अधिकृत किया था। नतीजतन, गांधी ने घोषणा की कि रविवार, 6 अप्रैल को रौलट एक्ट के विरोध में एक राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल (हड़ताल) देखी जाएगी। उन्होंने लोगों से एक दिन का उपवास करने के साथ-साथ बैठकें करने और विधेयकों के खिलाफ विरोध करने की भी अपील की।

6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में हड़ताल हुई। यह एक अनूठी सफलता थी, लेकिन दिल्ली की भीड़ पर पुलिस की गोलीबारी में कई लोग हताहत हुए। गांधी ने बंबई में हड़ताल का नेतृत्व करने का फैसला किया, और वे चौपाटी समुद्र तट पर पहुंचे जहां हिंदुओं, कई मुस्लिम, पारसी आदि सहित 1,50,000 लोग मौजूद थे। 'वन्दे मातरम् ' के नारों से वातावरण गूँज उठा। अपने भाषण में, गांधी ने दिल्ली में सत्याग्रहियों पर पुलिस की गोलीबारी का उल्लेख किया, और उन्होंने लोगों से यह वादा करने के लिए कहा कि जब तक अंग्रेजों का दिल नरम नहीं हो जाता, तब तक वे सविनय अवज्ञा से पीड़ित रहेंगे। इसके अलावा, कराची में व्यापारियों ने बंद कर दिया उनकी दुकानें, हिंदू और मुसलमान, पारसी, खोजा और जैन उस दिन उपवास करते थे। 20 पटना में, 6 अप्रैल को सभी दुकानें बंद रहीं, और शाम को एक बैठक में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

ढाका, मुर्शिदाबाद और मिदनापुर और कलकत्ता में रौलट सत्याग्रह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया । मद्रास ने भी पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया और शाम को 1,00,000 से अधिक लोगों ने एक बैठक में भाग लिया। लाहौर और अमृतसर में भी दुकानें बंद रहीं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता देखी गई। गांधी पंजाब के बारे में बहुत जागरूक थे। 8 अप्रैल को, वह दिल्ली के लिए एक ट्रेन में सवार हुए, जहाँ से उन्हें पंजाब जाने की उम्मीद थी, लेकिन पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया और वापस बॉम्बे भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के एक घंटे बाद लाहौर में दुकानें और बाजार बंद कर दिए गए। 9 अप्रैल की शाम को अमृतसर के दो प्रमुख कांग्रेस नेताओं सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आदेश जारी किया गया । उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांधी की गिरफ्तारी की खबर जब अमृतसर पहुंची तो सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। सरकारी बैंकों में आग लगा दी गई और तीन बैंक प्रबंधकों की हत्या कर दी गई। एक महिला मिशनरी को पीटा गया और मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया। इसके अलावा, भीड़ ने एक ट्रेन पर पथराव किया, और पुलों, टेलीफोन कार्यालय और डाकघर में आग लगा दी। 10 और 11 अप्रैल को हिंसा जारी रही। उसके बाद अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और ओ' ड्वायर ने सेना भेजी, और पुलिस की गोलीबारी में कुछ लोग मारे गए।

13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने सभाओं और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा जारी की। कुछ पुलिसकर्मियों को भी मेगाफोन के साथ सड़कों पर भेजा गया ताकि लोगों को किसी भी बैठक में शामिल न होने की चेतावनी दी जा सके। 13 अप्रैल की दोपहर जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। जनरल डायर उस स्थान पर पहुंचा और अपने सैनिकों को बिना किसी चेतावनी के पार्क में अज्ञात भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। परिणामस्वरूप, 1,000 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। 24 पंजाब में हुई क्रूरता पर पूरे देश में व्यापक गुस्सा था। इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी की बैठक में, गांधी ने सविनय अवज्ञा को निलंबित कर दिया क्योंकि सविनय अवज्ञा फिर से शुरू होने पर बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें हिंसा की धमकी दी थी। रवींद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया।

उन्होंने कहा: "समय आ गया है जब सम्मान के बैज अपमान के असंगत संदर्भ में हमारी शर्म को स्पष्ट करते हैं, और, मैं अपने हिस्से के लिए, अपने देशवासियों के पक्ष में सभी विशेष गौरव से दूर रहना चाहता हूं, जो उनके लिए -कहा जाता है कि महत्वहीनता मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण गिरावट का सामना करने के लिए उत्तरदायी है। जलियांवाला हत्याकांड के बाद, 27 दिसंबर 1919 को अमृतसर में कांग्रेस का 34वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। डॉ. हेडगेवार सहित पूरे भारत के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने सत्र में भाग लिया। डॉ. हेडगेवार जलियांवाला बाग के रक्तरंजित स्थल को देखने भी गए थे। अमृतसर अधिवेशन में सी आर दास सुधारों को अस्वीकार करने के पक्ष में थे, लेकिन तिलक उत्तरदायी सहयोग के पक्ष में थे।

अध्ययन का उद्देश्य

1. रौलट बिलों की शुरूआत के साथ राजनीतिक माहौल गंभीर हो गया ।
2. भारत की आजादी के पहले पांच दशकों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में आरएसएस की भूमिका कोई मुद्दा नहीं थी।

निष्कर्ष

आरएसएस हिंदुओं का एक पुरुष सांप्रदायिक संगठन है, जो "सर्वोच्च तानाशाही" के सिद्धांतों पर आधारित है। 32 इसलिए मरज़िया हिंदू राष्ट्रवाद की जड़ों पर काम करने वाले एक इतालवी शोधकर्ता कासोलारी ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला है कि "हिंदू राष्ट्रवाद के प्रमुख ऐतिहासिक संगठनों और नेताओं की फासीवाद और नाजीवाद में विशिष्ट और निरंतर रुचि थी। " इसलिए हम समझ सकते हैं कि आरएसएस का गठन नाजियों और हिटलर के उदाहरणों से प्रभावित और प्रेरित था। गोलवाकर का कहना है कि मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट हिंदू राष्ट्र के दुश्मन हैं। 33 इस कारण से वे मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं, जो उन्हें हिंदू संस्कृति का पालन करने की आवश्यकता और मांग करता है। आरएसएस राष्ट्रवादी और देशभक्त निकाय है और यह एक अर्धसैनिक संगठन भी है। इसलिए आरएसएस को सबसे सक्रिय संगठन के रूप में माना जा सकता है जो भारत में चल रहे अधिकांश मुद्दों में शामिल है।

संदर्भ

[1]। बिपन चंद्रा, कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 332.

1. देखें राकेश सिना , अंडरस्टैंडिंग आरएसएस, हरानंद पब्लिकेशंस प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली, 2019।
2. बिपन चंद्र, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरिएंट ब्लैकस्वान , नई दिल्ली, 2019, पुनर्मुद्रण, पीपी. 245-48।
3. बिपन चंद्रा, अमलेस त्रिपाठी और बरुण डे, फ्रीडम स्ट्रगल, नई दिल्ली, 2005, पुनर्मुद्रण, पीपी 79-80।
4. नीलांजन मुखोपाध्याय, द आरएसएस: आइकॉन ऑफ़ द इंडियन राइट, वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेनाई , 2019, पीपी. 3-4.
5. बिपन चंद्र, आधुनिक भारत का इतिहास, पीपी 250-51।
6. रमेशभाई महता , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लोटस प्रकाशन, मुंबई, 2019, पीपी. 45-46.
7. नीलांजन मुखोपाध्याय, द आरएसएस: आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट, पृ. 5.

8. राम लाल वाधवा, हिंदू महासभा , 1928-1947, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999, पीपी। 8-9।

9. नीलांजन मुखोपाध्याय, द आरएसएस: आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट, पृ. 6-7।

10. अरुण आनंद, द सैफरन सर्ज: अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आरएसएस लीडरशिप, प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली, 2019, पीपी। 18-19।

11. बिपन चंद्र, आधुनिक भारत का इतिहास, पृ. 273-75।

12. नीलांजन मुखोपाध्याय, द आरएसएस: आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट, पीपी. 13-14.